सामुदायिक स्वरोजगार योजनाओं का विकास

डॉ० सुनीता रानी

असिस्टेंट प्रोफेसर, स्याना डिग्री ,कालेज

स्याना, बुलन्दशहर , उ०प्र०

Email: drsunitarani@gmail.com

सारांश

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का उद्घाटन 1952 मे गॉधी की वर्शगाठ के दिन शुरू हुआ जिसका काम मोटे तौर पर नीति सम्बन्धी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों को तय करना और इनका निगरानी करना अमरीका में प्रशिक्षित इंजीनियर एस0के0 का सामुदायिक परियोजनाओं का प्रशासन नियुक्त किया गया। पंचवर्षीय योजना मे यह योगदान औसत 54 प्रतिशत थ इसके वाद यह लगातार कम हो गया 1961–62 तय तह केवल 20 प्रतिशत रह गया और अगले वर्ष और गिरकर सिर्फ 18 प्रतिशत ही रहा ये सरकारी आंकडे इस तय साफ और ऊपर लाते है कि आन्दोलन बनाने में असफल रही थी।

नेहरू महालनोबीस तथा दूसरे अधिकारियों ने चीन का दौरा किया और वहॉ जो हो रहा था। उसकी शानदार उपलब्धिया से वो बहुत प्रभावित थे चीनी जनता को बडे बाध बनाने सिंचाई तालाब खोदने मे लगा दिया था इसमें सारा काम शारीरिक श्रम या जनता की भागीदारी प्रति चीन और भारत समझ मे दो मूल करने के वाद से की इसने गॉवो मे सम्पत्ति सम्बन्धी को पूरी तरह से बदल दिया था। वहां पहली वार ऐसा हुआ था कि भूमि हीनों का शोषण करने के लिए भूस्तामी नही रह गया थे। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उंमग ओर उत्साह था।

पंचायती राज में बलवन्त राय मेहता सीमित के नाम से ज्ञात इस दल ने जनतान्त्रिक केन्द्रीय वाद को अपनी धुरी बनाया और तीन स्तरीय निकाय बनाने की सिफारिश की ग्राम पंचयात ब्लॉक पंचायत जिला परिषद पर बनाया अधिक जनसख्या ग्रामो में रहती है इसलिए नेहरू सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को एक मूल कान्ति कहकर पुकारा था इस देश को गरीब आदमियों की उन्नती न कि किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा अवसर इस योजना के द्वारा गरीबी और बेकारी का बोझ लोगों के कन्धों से हटा दिया जायगी। केवल कानून पास पार्लीमेंट गरीबी और बेकारी नही मिटा सका लोगो को खुद अपने असली को हल करने के लिए उकसाया गया है उन्हे संजीव चेतना ने प्रभावित किया है। उनकी ऑखो में चमक पैदा हुई उनके हाथो ने काम करना प्रारम्भ कर दिया।

मुख्य शब्दः *सामुदायिक विकास योजना, समुदायिक विकास कार्यक्रम का उदघाटन, नेहरू का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास, पंचवर्षीय योजना मे योगदान, जनता की भागीदारी, पंचायती राज, हमारी नदियों का बहुत सा पानी, योजना ऑफिसरों (कम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर्स)।*

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 05.08.2020
Approved: 27.09.2020

डॉ० सुनीता रानी

सामुदायिक स्वरोजगार योजनाओं का विकास

RJPP 2020,
Vol. XVIII, No. II,
pp.167-176
Article No. 20

Online available at *:*
https://anubooks.com/?page_id=6391

डॉ० सुनीता रानी

प्रस्तावना

सामुदायिक विकास योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही हमारी मुख्य देने थी। सामुदायिक विकास योजना तथा भूमि सम्बन्धी सुधार नामक महत्वपूर्ण कदम नेहरू द्वारा प्रथम योजना काल में ही उठाए गए थे। नेहरू का यह विश्वास था कि यदि विकास कार्य में शीध्र हो सकता है। सामुदायिक विकास और पंचायती राज का प्रारम्भ ग्रामीण जनता के जीवन में सुधार लाने के साथ –साथ सहायता कार्यक्रमों में लोगो को सीधे तौर पर शामिल करके इन कार्यक्रमों को स्वंय चलित बनाने के उद्देश्य से किया गया था। सामुदायिक विकास का विचार देश के लिए नया नही था। लाभ के लिए तमाम समुदाय किसी न किसी रूप में सामूहिक प्रयास करते रहे हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधियों में सरकार की सांझेदारी पर जोर सर्वप्रथम सन् 1928 ई0 रापल कमीशन और एग्रीकल्चर (शाही कृषि आयोग) ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई राज्यो में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाए शुरू की गए। लेकिन सारे देश में इसकी शुरूआत सन् 1951 में फोर्ज फाउंडेशन की सहायता से हुई इसके प्रारम्भ में परियोजनाओं को चलाने में मदद देने का प्रस्ताव किया था। इसी वर्ष भारत में अमेरिका राजदूत चेस्टर बॉवल्स ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए 5 करोड डालर की सहायता देने का प्रस्ताव रखा। अतः 50 सामुदायिक परियोजनाओं को चालू करने के लिए 1952 में भारत ने अमरीकी सरकार के साथ एक तकनीकी सहयोग समझौता किया। अमरीका ने जीप सिनमे प्रोजेक्टर ट्रैक्टर रोड रोलर जैसे आवश्यक साजोसमान की आपूर्ति करना स्वीकार किया। फोर्ड फांउडेशन के एक विशेषज्ञ डगलस एंसमिंगर इस कार्यक्रम के साथ गहराई से जुडे और नेंहरू तथा एस0के0डे0 दोनो के मित्र बन गए।

समुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 1952 में गांधी की वर्षगांठ के दिन शुरू हुआ। नेहरू ने कहा था जो काम हम आज षुरू करने जा रहें है वो मातृभूमि की सेवा में है आवश्यकता पडने पर हम अपना खून भी बहा सकते हैं जिससे कि हमारे देश के लोग आगे और भी जोरदार हो सकती है। मेरा विचार है कि पिछले वर्षों के दौरान किसी भी देश या दुनिया – भर में अपनी विषयवस्तु में इतना विशाल और उद्देश्य में इतना क्रान्तिकारी कुछ भी नही हुआ है जितना की भारत का यह सामुदायिक विकास हुआ।

समुदायिक विकास कार्यक्रम को योजना आयोग के अर्न्तगत रखा गया था जिसका काम मोटे तौर पर नीति सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्तों को तय करना और इनकी निगरानी करना या अमरीका में प्रशिक्षित इंजीनियर एस0के0डे0 को सामुदायिक परियोजनाओ का प्रशासक नियुक्त किया गया। इनके निर्देशन में निष्पादि नीला खेंडी परियोजना से नेहरू बहुत प्रभावित थे। मनुष्य के सम्पूर्ण विकास की यह एक एकीकृत योजना ग्रामीण जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण पक्ष को छूती थी कि जनता की लगातार चलने वाली भागीदारी से यह परियोजना एक जन आन्दोलन का स्वरूप ग्रहण कर लेगी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में तीन नए काम शुरू किए। पहली चीज एक सुसम्बन्ध खण्ड की धारणा थी जिसके लिए खण्ड विकास अधिकारी के अधीन कर्मचारी नियुक्त किए गए। दूसरे राज्य स्तर पर ताल मेल बिठाने के लिए एक विकास आयुक्त

बनाया गया। यह अधिकारी कार्यक्रम का एक प्रकार से सर्वेसर्वा था और तीसरे या ग्रास स्तर का कर्मचारी जिसे ग्राम सेवक कहा जाताा है। यह बहुधन्धी कार्यकर्ता जो लगभग 10 गांवो के लिए खण्ड या ब्लॉक योजनाओं को पहुॅचानें का काम करता। जिला स्तर पर इसका प्रभारी सर्वव्यापी सदा व्यस्त रहने वाला कलेक्टर था इसका काम अपने अधीन मे तमाम खण्डों के प्रशासन की देखभाल करना और साथ ही अपने जिले में नियुक्त विशेषज्ञों को गतिविधियों मे तालमेल बिठाना था। कार्यक्रम की अवधारणा का विकास केन्द्र सरकार के स्तर पर किया गया और इसकी व्यवहारिक आवश्यकताओं का निर्धारण योजना आयोग ने किया। 1956 में सामुदायिक परियोजना प्रशासन की मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया ओर एस0के0डे0 इसके मंत्री बनाए।

समुदायिक विकास योजना नेहरू का पहला राष्ट्रव्यापी प्रयास था। जिसका उद्देश्य स्वंय सहायता की संस्कृति और भागीदारी प्रजातन्त्र को प्रोत्साहित करना था। उन्होने इसका वर्णन उद्देश्यों में क्रान्तिकारी के रूप में किया था। उस समय तक औपनिवेशक प्रशासन की पितृवत अवधारणा कि जनता के कल्याण का एकमात्र संरक्षक सर्वज्ञ राज्य है। लेकिन सामुदायिक विकास ने लोगों को उत्तरदायी वयस्क माना जो अपने सर्वश्रेष्ठ हितों को अच्छी तरह समझ सकते थें और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने की कोशिश की गई। लेकिन सदियों से अभावग्रस्त रहने के कारण उनका बाहरी सहायता की जरूरत थी कि वे आत्मनिर्भर बन सके। ऐसी स्थिति में राज्य ने उत्प्रेरक का काम किया। इसलिए यह अनिवार्य कर दिया कि ग्रामीणों के कल्याण के लिए बनाई गई प्रत्येक योजना की आधी लागत अपने श्रम (श्रमदान) सामग्री या नकदी रूप में अदा करें इस तरह के योगदान के बगैर लोग नई सामूहित परिस्थितियों के पैदा होने में अपनी भागीदारी का अनुभव नहीं करेंगे।

नेहरू को पूरा विश्वास था कि यह कार्यक्रम जन– आन्दोलन बन जाएगा । लेकिन ऊपर से नीचे तक अवधारणा से क्रियान्वयन तक यह पूरे तौर पर सरकारी कार्यक्रम था। इसकी योजना सरकारी एजेन्सियों ने तैयार की थी । इसके लिए अधिंकाश धन सरकार ने दिया था और लागू करने के मामले में यह कलेक्टरों और खण्ड विकास अधिकारयों के सहारे थी। सरकारी नियन्त्रण इतना कडा था कि काफी समय तक खण्डो के योजना सम्बन्धी बजट का निर्धारण योजना आयोग के द्वारा ही किया जाता और इसको स्थानीय परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकारें तक बदल नहीं सकती थी कि प्रत्येक स्तर पर गैर–सरकारी लोंगो और जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था लोग जानते थे कि अधिकारी और पैसा कहॉ से आ रहा था।

कभी–कभी मैं उक्त नेतृत्व के बारे में सन्देह करने लगता और थोडा चिन्तित भी हो जाता हूॅ जो हम मेरे सहित दे रहे। मेरा विचार है कि खुद लोगों को यह अवसर देना चाहिए कि वे इसके (सामुदायिक विकास) बारे में सोच सकें। इससे हमारी सोच पर असर पडेगा बडी–बडी इमारतों और कार्यालों में बैठकर हम यह सोचने लग सकते है कि काम तो हम भी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहें। यदि सामुदायिक विकास योजना जनसाधारण को उत्साहित नहीं कर पायी या उनका पूरा सहयोग प्राप्त नहीं कर सकी तो इसमें कोई आर्श्चय की बात नहीं। जनता का

पचास फीसदी योगदान भले ही मिल पा रहा था और अधिकारी पर लक्ष्य पूरे करने का दबाव था। सरकारी नियमों का पालन करने के लिए स्वंय सेवी काम का मूल्य बढा दिया गया। कुछ काम सरकारी कृपा पर चलते स्थानीय ठेकेदारों से कराए गए और उनको श्रमदान के खाते में डाल दिया गया कुछ मामलों में तो स्थानीय बडें लोगों ने गांव वालो से जबरदस्ती कराया था। ग्रामीण उन योजनाओं ने अपनी मेहनत का भी योगदान करना नही चाहतें थें। जिनसें उनके गॉव का भला हो सकता था तो इसके पीछे ठोस कारण ये खेती की नालियॉ बनाने बाधॅ पर मिट्टी डालने या छोटी सिंचाई योजनाओ पर काम करने से एक गरीब भूमिहीन मजदूर को क्या मिलने वाला था जबकि उसके पास साथ–भर जमीन तक नहीं थी । स्कूल की इमारत या पंचायत घर बनाने में उसे पंचायत का सदस्य चुना जाने वाला नहीं था। सड़क बनाना आवश्यक ही उपयोगी था। लेकिन जिस आदमी ने कभी अपना गांव छोडकर दूसरा गांव न देखा हो और जिसके पास मण्डी तक ले जाने को कुछ हो। सभी नहीं उनके लिए सड़क का क्या मतलब हो सकता था।

पंचवर्षीय योजना में यह योगदान औसतान 54 प्रतिशत था। इसके बाद यह लगातार कम होता गया । 1961–62 तक यह केवल 20 प्रतिशत रह गया और अगले वर्ष और गिरकर सिर्फ 18 प्रतिशत ही रहा । ये सरकारी ऑकडे इस तथ्य को साफ और ऊपर लाते है कि सरकार सामुदायिक विकास को एक जन–आन्दोलन बनाने में असफल रही थी । सामुदायिक विकास योजना के मूल में ही दोष था यह दो घोडों पर एक साथ सवारी करना चाहती थी। इसकी संकल्पना और पहल अमरीकी सरकार और फोर्ड फाउंडेशन की ओर से हुई थी उनका आदर्श उनकी अपनी विस्तार सेवा थी इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढाना था । उनके कर्मचारी ने साक्षर किसानों को कृषि की उन्नत विधियों और नए उपायों की उपयोगिता प्रदर्शित करने के लिए भूखण्ड बनाए और वो आवश्यक जानकारिया प्रदान की थी जिन को किसान चाहते थे। तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अमरीकी सरकार ने भारत की जीपों टैक्टरों और लालटेनों की आपूर्ति की और फोर्ड फाउण्डेशन ने दिया एक रोबदार सलाहकार या हूॅ कहे कि अमरीका ने वो दिया जो दे सकता था उसकी समझ में भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की भारत की समस्या की प्रकृति मूलयता तकनीकी थी और भारत के सामुदायिक कार्यक्रम की धुरी भी यही समझ बन गई। इसमें जनता की भागीदारी और मातृभूमि के लिए खून बहाने वाली लफ्फाजी भी शामिल थी ।

नेहरू महालनोबीस तथा दूसरे अधिकारी ने चीन का दौरा किया और वहॉ जो हो रहा था उसकी शानदार उपलब्धियां से वो बहुत प्रभावित था। चीनी जनता को बडे बडे बांध बनाने सिंचाई तालाब खोदने में लगा दिया था। इसमें सारा काम शारीरिक श्रम से आधुनिक मशीनों के बगैर किया गया था जनबल चीन का सबसें बडा संसाधन था और वह इसका इस्तेमाल बडे कारगर ढंग से कर रहा था। अतः यह योजना बनाई गई कि सामुदायिक परियोजनाओं को पूरा करने तथा ऐसे ही दूसरे कामों में भारतीय जनता को शामिल किया जाये चलते दूसरी चीजों के अलावा उनकी गरीबी दूर और उनके सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आए। ठोस योजनायें बनाई गई। कार्यकर्ताओं की फौज भर्ती की गई और उनके लिए सैकडों करोडों रूपयों का

आबंटन किया गया। लेकिन भारत के नियोजकों और नेताओं के हाथ निराशा ही लगी।

जनता की भागीदारी के प्रति चीन और भारत समझ में दो मूल करने के बाद शुरू की। इसने गॉवो में सम्पत्ति सम्बन्धी को पूरी तरह से बदल दिया था। वहॉ पहली बार ऐसा हुआ था। कि भूमिहीनो का शोषण करने के लिए भूस्वामी नही रह गए थे। चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी उमंग और उत्साह था। भारत में हुए ग्राम सुधारों में भारी संख्या में भूमिहीनों और सीमान्त किसानों को कोई लाभ नही हुआ था। इसलिए भूमि सुधारों से गावो में कोई जोश नही था। स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विराट जन– आन्दोलन नहीं देता था। आजादी के बाद इस शक्तिशाली पार्टी का सबसे लाभप्रद रूप से इस्तेमाल राष्ट्र– निर्माण के लिए किया जा सकता था। लेकिन नेहरू ने इसे जंग लगने दी और बर्बाद होने दिया। इसके स्थान पर अपने विकास कार्यक्रम को लागू करने की बागडौर औपनिवेशिक अफसरशाही के हाथों सौप दी।

उन्होनें सामुदायिक परियोजना सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा उनमें अफसरों में उद्देश्य की भावना काम करने की व्यग्रता कैसे भरी जाए कार्यक्रम लागू करने के लिए अधिक जोष से और उस भावना के साथ काम करना होगा जो किसी राष्ट्र को ऊचें लक्ष्य की ओर ले जामती है। और देश के ग्रामीण क्षेत्रो को नई दृष्टि देने के लिए नेहरू पेशेवर अफसरशाहों के दिलो में एक चिंगारी की तलाश करते रहे थे। नेहरू सिद्धान्त और राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। विकास आयुक्त जिला कलेक्टर और खण्ड विकास अधिकारी सांसरिक दिनचर्या के क्षेत्र में काम करते है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक आचरण के नई तौर तरीकों का विकास करने के लिए जनता को संगठित और आन्दोलन करने का काम पूरे तौर पर उनके छूते के बाहर की चीज है। यह दुःख और जानते हुए भी विकास और सामाजिक रूपान्तरण के औजार के रूप में उनका चयन किया।

नेहरू की तमाम विशाल परियोजनाओ में सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियॉ सबसे साधारण थी। खाद्य की पदार्थो की स्थिति खराब होती हुई खेती पर जोर बढता गया । लेकिन विडम्बना यह रही कि इस क्षेत्र में भी कुछ अधिक हासिल न हो सका और खाद्यानों के आयात की मात्रा लगातार बटती गई गरीबों की स्थिति सुधारनें उनके सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने या अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के मामलें में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली सामुदायिक विकास योजना इस विशाल स्तर पर के अभूतपूर्व प्रयोग थी। अफसरशाही के लिए उसे एक सेवा की एजेन्सी की भूमिका में टालने का इस तरह का पहला प्रयोग था। गांवो –गांवों में झुण्ड के झुण्ड विकास कर्मचारी परिवर्तन के एजेटों के रूप में फैल गए थे। अतीत में ग्रामीणों के लिए सरकार अधिकतर दूर की एक निराकार चीज थी। उन्होंनें इनकों अपने बीच काम करते समस्याए सुलझाने और उनकी जरूरतों पर ध्यान देते देखा था।

सडकों तालाबों स्कूली इमारतों इत्यादि के निर्माण ने ग्रमीण क्षेत्रों में हलचल मचा दी थी और आर्थिक गतिविधि को तल कर दिया था। प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रों ने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति अधिक जागरूकता फैलाई और बीमारियों से राहत दी ।

पंचायती राज – सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जी परिणाम और विशेषतया जनता

को शामिल करने में इनकी विफलता के कारण भागीदारी जनतन्त्र में एक ऐताहिसक प्रयोग की शुरूआत हुई। 1957 में सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के काम काज का जायजा लेने के लिए एक अध्यन दल की नियुक्ती की बलवन्त राय मेहता समिति के नाम से ज्ञात इस दल ने जनतात्रिक केन्द्रीयतावाद को अपनी धुरी बनाया और तीन स्तरीय स्थानीय निकाय बनाने की सिफारीश की। इन तीन निकायों को ग्राम स्तर (ग्राम पंचायत) खण्ड या ब्लाक स्तर (ब्लॉक पंचायत) आर जिला स्तर (जिला परिषद) पर बनाया जाना था। प्रत्यक्ष चुनाव केवल ग्राम स्तर पर होने थे। ऊपर के दो स्तरों का गठन ग्राम पंचायतों तथा ब्लाक समितियों के अध्यक्ष द्वारा किया जाना था। नियोजन तथा संगठन के लिए लोक स्तर की समितियों की मुख्य भूमिका थी। इन समितियों को प्रभावशाली बनाने के लिए इनको समुचित प्रशासनिक आर्थिक अधिकार दिए जाने की सिफारिश की गई पंचायती सस्थओं का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि ये अपने कामकाज ने स्वायत थी। किसी भी स्तर पर इन संस्थाओं पर अफसरशाही हावी न हो । ग्राम पंचायत सचिव को वेतन देती थी। ब्लॉक समिति के मामलों में इसके सचिव का काम ब्लॉक विकास अधिकारी करता था। जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो प्रायः भारतीय प्रशासनिक सेवा को होता जिला परिशद अध्यक्ष के अधीन काम करता था।

जिन तमाम परियोजनाओं के बारे मे नेहरू ने सोचा था। उनमें से इनको सबसे कम धनराशि और बहुत थोडी राजकीय सहायता की आवश्यकता थी। यह जनता पर निर्भर थी। लेकिन यही सबसे बडी कमजोरी साबित हुई जनता के सत्ताधारी प्रतिनिधि अपनी ताकत को जनता के दूसरे प्रतिधिनिधियों के साथ बांटने को बेहद अनिच्छुक रहते है पंचायत के तीनों स्तरों निर्वाचित सदस्य शीघ्र ही विधायकों को दौडाती थी कि पंचयातों के बडे लोगों के झुण्ड तरह –तरह की सहायता लेने मांगने वाले विधायको की कतार में शामिल हो जाए कि अपने – अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के साथ पंचायती नेताओं का सीधा सम्वाद था। और वे व्यक्तित्व रूप से सहायता करते थे। इससे विधायकों के कान खड़े हो गए और मुख्यमन्त्री पर दबाव डाला और इस तरह से पंचायतों को परकेज कर दिया गया इसके अलावा इन बीजों का दर्जा ऊंचा करने के लिए राज्य मन्त्रियों को इनका अध्यक्ष बना दिया जहां महाराष्ट्र ने अपना सब कुछ टेढे मेढे रास्ते से सीखा वहां दूसरी राज्य सरकारें शुरू से ही सावधान रही उन्होनें पंचायतों को न तो कोई महत्वपूर्ण काम सौंपे और न ही कोई अधिकार या धन दिया। खंड और जिलास्तर ही नही था। वैसे भी कागज पर योजना तैयार करने का काम गांव वालों के लिए बहुत अमूर्त और मुश्किल है। लोगो को स्थानीय स्तर पर अपने मामलें खुद निपटाने की आजादी के अर्थों में जनवाही केन्द्रीयता का दूर का एक सपना बनी रही।

पंचायतों को अधिक आजादी और अधिकारी से शक्ति सम्पन्न न करने के लिए वो ही तर्क दिये गए जो अंग्रेज भारत को स्वतन्त्रता नही देने के लिए देते थे। राजनीति और अफसरशाही दोनों के उच्च स्तरों पर यह सोचा जाता था कि रिश्तेदारियों के जाल में फसें तथा जातिगत वफादारियों और व्यक्तिगत लालच के चलते एव प्रशासनिक कामकाज में प्रशिक्षण के अभाव में

पंचायतें भ्रष्टाचार भाईचारा और गुठमुन्दी के अडडे बन जायेगे। तीसरी दुनिया सबसे स्थिति प्रजातन्त्र में जहां उनकी दूरदर्शिता बाहर दिए गए और जो बचे वे अपने भविष्य के बारे में बहुत भयभीत है।

कश्मीर को गलती से हिन्दुस्तान या पाकिस्तान के लिए एक लूट खसोट की चीज मान लिया गया है। लोग यह भूल गये कि कश्मीर बिक्री या सौदे की चीज नही है। उसकी अपनी अलग हैसियत है और उसके भविष्य का फैसला करने वाले उनके लोग ही होगें। आज संघर्ष चल रहा है–लडाई के मैदान में नही बल्कि लोगों के दिमागों में यह संघर्ष बंटवारें से बहुत बरस पहले शुरू हुआ था। हिन्दुस्तान मुस्लिम लींग के नेतृत्व में सामप्रदायिक आन्दोलन बंटा और दो राष्ट्र का सिद्धान्त के समर्थको ने कश्मीर की सुन्दर घाटी के हड़प लेने की कोशिश की। वे नाकाम रहे और तब कश्मीर में मजबूत राष्ट्रीय आन्दोलन पैदा हुआ। जिसकी एक निश्चित विचारधारा थी और जो सामाजिक रूप से बहुत आगे बढी हुई थी। कश्मीर की नेशनल कान्फ्रेस ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया और उसे भारतीय कांग्रेस तथा देशी राज्य– परिषद के आन्दोलन के साथ बहुत सी बातो में एकरूपता दिखाई थी कि कश्मीर के लोग पाकिस्तान संकीर्ण साम्प्रदायिकता का मुकाबला करते जो कि उन पर हिंसा और ताकत के जोर पर लादी जा रही थी। हिन्दुस्तान के लोगों के लिए स्वाभाविक और अनिवार्य था कि तकलीफ में उनका साथ देते।

उस सपूत की तरफ जिसे हिन्दुस्तान ने पैदा किया आजादी की लडाई का एक बडा नेता जिसने इस लडाई के लिए और सामान्य आदमियों की सेवा के लिए अपना जीवन ही समतिर्पत कर कर दिया वह आदमी है अब्दुल गफ्फार खा। वह और उनके बहादुर साथी पाकिस्तान की जेल में साल पर साल अपनी जिन्दगी बिता रहे हैं कि उनका देश आजाद हो गया है। यह एक न सिर्फ महत्व की बात है बल्कि इस बात का प्रतीक भी है कि पाकिस्तान में बहादुर और आजादी से प्रेम करने वाले लोगों को किस तरह की स्वतन्त्रता मिलने वाली है इसलिए हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ताना सम्बन्धों के रास्ते में कश्मीर नही बल्कि एक बहुत गहरा झगडा आ जाता है। हम उन बुनियादी आदर्शों को नही छोड सकते जिनकों कि अब तक मजबूती से पकडे रहे हैं और जिन पर हमारे राज्य की सारी मान्यता स्थापित है हम ऐसी किसी चीज को प्रोत्साहन नही दे सकते जो कि हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता को छिन्न – भिन्न करती हो। हम फूट और आक्रमण की पुरानी नीति को जारी रखने के लिए तैयार नहीं हो सकते। इस बात का साफ साफ समझ लेना चाहिए पाकिस्तान के साथ दोस्ती के सम्बन्धों की आवश्यकता को हमने महसूस किया है और हम उसके लिए बराबर कोशिश करेंगे लेकिन वह दोस्ती तभी कायम हो सकती है जबकि पाकिस्तान आक्रमण की भावना छोड दे।

हमारे सविंधान की मर्यादाओं में तथा मौजूदा सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बिना छिन्न – भिन्न किये जो साधन हमें मिल सके । उन्हीं की मदद से जो कुछ किया जा सकता है। इस योजना ने एक महत्वपूर्ण सेवा यथार्थ रूप में यह बता कर की अगर हम अपना दिल और दिमाग लगायें तो क्या कर सकते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना हमारे लिए मुमकिन नही है। हमारे उद्देश्य हमारी बडी –बडी उम्मीदों और हमारी कल्पनाओं का यदि ठोस

वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है तो वे हवाई किले की तरह रह जाती है और उससे हम भ्रम में पड जाते है। यह योजना लोगों को न सिर्फ उद्धेश्यों की बाबत कि उन उद्धेश्यों को कैसे प्राप्त कर सकते और हमारे साधन क्या है। लोगों के विचार कुछ भी हो मेरा ख्याल है कि आगे की निश्वत सोचनाा या योजना तैयार करना बहुत कुछ इस पंचवर्षीय योजना पर निर्भर करता है। हमारी नदियों का बहुत –सा पानी बेकार चला जाता है जबकि हमें पानी दूसरी जगह पर आवश्यकता होती है। हम बांध बाधते हैं, तालाब बनाते हैं जिससे इस पानी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और अपनी जमीन की सिचांई कर ले व बिजली बगैर पैदा कर लें कि ऐसे समय में जबकि अधिक उपज की आवश्यकता है। बहुत – से लोग बेकार बैठे हैं कि उससे कहा तक हमारें उन करोडों लोगो को राहत पहुॅचती है जो मुश्किल से अपना पेट भर पाते। हमारे संविधान में सही तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि हम अपनी दलित जातियों आदिवासियो तथा आर्थिक दृष्टि से पिछडे हुए अन्य वर्गों को ऊपर उठाये अपने लोगों का सामान्त स्तर ऊॅचा कर सकते हैं। हमें इस दुर्भग्यपूर्ण बात याद रखनी चाहिए कि आर्थिक उन्नति ये हमारी लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य बन जाते हैं। हमारी राजनैतिक आजादी के बाद हमारी यात्रा की यह दूसरी अहम मंजिल है। यह मंजिल हम सामजिक और आर्थिक योजना बनाकर ही तय कर सकते है जिससे कि हमारे साधनों का इस्तमाल ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए हो सके और वे साधन यथा संभव तेजी से बढाये जा सके। इस मंजिल को हम भविष्यता या निजी प्रयत्नों के मनमानेपन अथवा स्वार्थ भावना के भरोसे छोडकर पार नहीं कर सकता पिछली लडाई और उसके बाद देश में हमें समाज विरोधी प्रवृत्तियों को रूप में काली दुर्भाग्य का सामना करना पडा है। उसका मुकाबला अब हमे सुसंगठित आधार पर तथा जहां जरूरी हो वहा नियंत्रण करके करना है। नियंत्रण कई भी पसन्द भी नही लेकिन जब लोगो की संग्रहवृत्ति सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाती है तो कुछ चीजों पर अकुंश जरूरी हो जाता है इसलिए निजी प्रयत्न राष्ट्रीय योजनाओं के सांचे में ढलने चाहिए उन्हे प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

सामुदायिक विकास योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना की ही मुख्य देन थी सामुदायिक विकास योजना तथा भूमि सम्बन्धी सुधार नामक महत्वपूर्ण कदम नेहरू द्वारा प्रथम योजना काल में ही उठाए गए थे। नेहरू का यह विश्वास शीध्र हो सकता है। देश की अधिकांश जनसख्या ग्रामों में रहती है इसलिए नेहरू सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना को योजना मंत्री सुरेन्द्र कुमार डे ने एक मूल क्रांति कहकर पुकारा था। वास्तव में यह एक मूक क्रांति ही थी क्योंकि इसकी ओर भारत का प्रेस भी उदासीनया जबकि इसके द्वारा उन गांवों का जो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार है नक्शा ही बदला जा रहता था। नेहरू इस बात को स्वीकार करते थे। भारत की प्रगति नहीं हो सकी और शहरों को प्रगति हो गई तो शहर एक क्रांति तबाह हो जायेंगें नेहरू यह देखकर दुःखी थे कि भारत के नौजवान करना चाहिए और ग्राम सेवा कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए।

नेहरू जानते थे कि भारत में शहरों का विकास तो भारी उद्योगों के विकास से हो जायेगा गांवों की समस्या शेष रहेगी। वे गावों की समस्या को सुलझाने के लिए बडे उत्सुक थे।

अतः गांव के सर्वागीण विकास को ध्यान में रखकर ही नेहरू की देख रेख में योजना आयोग में सामुदायिक विकास योजना का प्रारूप तैयार किया गया था। उन्होंनें कहा था कि जो कार्य हमनें आरम्भ किया है वह कान्ति को जन्म देने वाला होगा। एक स्थान पर उन्होनें कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा बिजलीघर है पांच साल योजना की कामयाबी से पूरा करने के लिए प्रेरक शक्ति सामुदायिक देता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम एक ऐसा बिजलीघर है। पांच साल योजना की कामयाबी पूरी करने के लिए प्रेरक शक्ति देता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य औसत आदमी के रहन – सहन के स्तर को ऊचा उठाना है। यह बडे महत्व का सवाल है कि शन्ति शक्तिमय ढंग से कर सकते है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ आस्था की एक आभा जुड़ी हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयन्ती के अवसर पर 55 चुने हुए क्षेत्रों में लागू किया गया भारत में इस कार्य के लिए प्रमुख सलाहाकार के रूप में नेहरू ने फोर्ड फाउन्डेशन के प्रतिनिधि डा0 डगलस एन्सिजर को नियुक्त किया था। इसका लक्ष्य के गावों को स्वावलम्बी ग्राम बनाना था। ऐसी ही गांधी जी की इच्छा थी। भारत में 32 करोड 50 लाख जनता लगभग 6 लाख गांवों में निवास करती थी। द्वितीय योजना काल में विदेशी मुद्रा संकट बीच में आ पड़ा। सामुदायिक विकास योजना का आधारभूत एकांश लगभग 100 गांवों और 60000 से 70000 तक जनता का विकास खण्ड रखा गया था। विकास आयुक्त राज्य मत्रांलय से निर्देश प्राप्त करता था। सम्पर्ण भारत के लिए केन्दीय सरकार का सामुदायिक विकास योजना की नीतियों को कायन्वित कराने कार्य ग्राम से तक (ग्रामीण स्तर कार्यकर्ता) के हाथ में होता था जो लगभग 10 गांवों के लिए उत्तरदायी होता था और हेडक्वार्टर इन्ही में से एक गांव में होता था।

सामुदायिक विकास योजना ने क्षेंत्रीय कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों के मन में यह बिठाना था कि नये ढंग से खेती करने का चिकित्सालय का नई सडकों का और अपने श्रम को सहकारी संस्थाओं में लगाने का क्या भौतिक लाभ होगा किसी विषय पर कोई निश्चित करने का काम गांव प्रयोजन हाथ में नही ली जा सकती थी। ग्रामीण जनता जागरूक होगी। ग्रामीणों के निजी गरिमा को एक नई भावना का दय हो सकता था और वे उस नागरीय जीवन से जिसमे वे सैकडो वर्शो से फंसे हुए थे। नेहरू को यह आशा ही नही पूर्ण विश्वास था कि धीरे धीरे इस योजना द्वारा एक स्वाभिमानी ग्रामीण समाज का उदय होगा।

योजना ऑफिसरों (क्मयूनिटी प्रोजेक्ट ऑफीसर्स) ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम को शुरू किया है। इस योजना के पीछे जो विचार है वह एक बीज की तरह है। इस बीज में से कतला फूटेगा और अंत में वह एक विशाल वृक्ष के रूप मे विकसित होगा जिसकी छाया में इस देश लाखों व्यक्ति आश्रय ले सकेगें। योजना ऑफिसरों को इस कार्य के महत्व को समझ लेना चाहिए। उसका अर्थ है इस देश के गरीब आदमीयों की उन्नती न ही किसी एक व्यक्ति के लिए अच्छा अवसर। इस योजना के द्ववारा गरीबी और बेकारी का बोझ लोागों के कन्धों से हटा दिया जायगा। केवल कानून पास करके पार्लियामेंट गरीबी और बेकारी नही मिटा सकती लेकिन आखिरकार आदमियों की कोशिश से देश आगे बढता है। हिन्दुस्तान का सवाल यह कि

35 करोड़ आदमी इस रास्ते की तरफ कैसे बढे हमें लोगों में उमग पैदा करनी है। जिससे कि वे भविष्य की तस्वीर को देख सके और उस दिशा में आगे बढ सकें। यही देश की सबसे बढी ताकत है। इस समय 55 सामुदायिक योजनाएं आरम्भ की गई है। धीरे –धीरे इन योजनाओं के लिए और स्थान भी चुने जायेगें और सख्या 500 तथा उससे ऊपर भी जा सकती है। इस तरह की योजना आखिरकार हिन्दुस्तान के हर गांव में हों। काम बडा और शायद उसकी कल्पना भी इससें पहले नही की गई।

बल्कि लोगों को खुद अपने मसलों को हल करने के लिए उकसाया गया है। उन्हें सजीव चेतना ने प्रभावित किया है। उनकी आंखों में चमक पैदा हुई । उनके हाथों ने काम करना प्रारम्भ किया है और उनकी मांसपेशिंया मजबूत हुई। योजना की आशिंक सफलता का मूल्यांकन करते हुए बीयर का भी यह मत है कि 66 इस योजना से ग्रामीण नयें कार्यक्रम की ओर उन्मुख हुए वे परिर्वतन चाहते हैं। उनके बीबी–बच्चों की आर्थिक देखरेख होती है। उनकी भूमि अधिक उपजाऊ होती है। कुछ लोग उदासीन हैं अन्य लोग अब भी गहरातियों और अधिकारियों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। कुछ और लोगों का ख्याल है कि सुधार की रफ्तार ज्यादा तेज है। यह मूल रूप से कल्याणकारी उपलब्धी है और इसी भारत में लोकतन्त्र की जडे मजबूत हो सकती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. जवाहरलाल नेहरू – *आटोबायोग्राफी हिन्दु मुस्लिम ऑल इण्डिया* नई दिल्ली पृ0– **145**
2. लक्ष्मण सिंह – *आधुनिक भारतीय राजनीति एंव सामाजिक विचार* कॉलिज बुक डिपो सन् 1971 पृ0 **30**
3. जवाहर लाल नेहरू – *सामुदायिक विकास और पंचायती राजनीति* पृ0 **40**
4. माईकल ब्रीचर – *स्पेसिफिक सोरसिज ऑफ इण्डिन न्यूटलीज* सन् 1977पृ0 **50**
5. माड. तिवोर – *मै नेहरू से मिला,* राजकमल सन् 1950 पृ0 **88**
6. जवाहरलाल नेहरू – *विश्व इतिहास की झलक* सम्पादक वार्ष्णीय मण्डल नई दिल्ली तृतीय संस्करण 1965 पृ0 **145**
7. के0पी0 मिश्रा – सम्पादक *फोरन पॉलिसी ऑफ इण्डिया* नई दिल्ली सन् 1977 पृ0 **22**
8. जवाहरलाल नेहरू – *मेरी कहानी* पृ0 **180**